

राज्य में प्रथम महिला नधि वित्तीय संस्थान के लिये एमओयू

चर्चा में क्यों?

25 जुलाई, 2022 को राजस्थान में प्रदेश का पहला और देश का तीसरा 'महिला वित्तीय संस्थान' स्थापित करने के लिये ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीणा की उपस्थिति में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद एवं स्त्रीनधि तेलंगाना के मध्य एक एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए।

प्रमुख बिंदु

- इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में हुए इस एमओयू पर राजीविका की ओर से राज्य मशिन नदिशक मंजू राजपाल एवं तेलंगाना की ओर से स्त्रीनधिके एमडी जी. वदियासागर रेड्डी ने हस्ताक्षर किये।
- राज्य में 'राजस्थान महिला नधि' की स्थापना तेलंगाना राज्य में सफलतापूर्वक संचालित स्त्री नधि मॉडल की तरज पर राज्य स्तरीय सहकारी वित्तीय संस्था के रूप में राजीविका के माध्यम से की जा रही है। राजीविका के क्लस्टर लेवल फेडरेशन इसके सदस्य होंगे।
- राजस्थान महिला नधि की स्थापना के लिये राज्य सरकार द्वारा दो वर्षों में कुल 50 करोड़ रुपए (प्रथम वर्ष में 25 करोड़ रुपए) का अनुदान दिया जाएगा एवं भारत सरकार से 110 करोड़ रुपए के अनुदान हेतु प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्रेषित किये गए हैं।
- इस नधि के संचालन के लिये चरणबद्ध तरीके से राजीविका द्वारा 561 प्रोन्नत संकुल स्तरीय संघ (क्लस्टर लेवल फेडरेशन) से 10 लाख रुपए प्रति संकुल स्तरीय संघ शेयर कैपिटल के रूप में योगदान दिया जा रहा है।
- महिला नधि के माध्यम से 40,000 रुपए तक के ऋण 48 घंटे में एवं इससे अधिक राशिके ऋण 15 दविस की समय सीमा में वितरित हो सकेंगे।
- इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री रमेश चंद मीणा ने कहा कि महिला नधि की स्थापना के बाद राजीविका के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को बल मल्लिगा और उन्हें अपने उद्यम के लिये ऋण प्राप्त करने में सहूलयित होगी। बैंकों में लंबति ऋण आवेदनों की संख्या में भी कमी आएगी।
- राजस्थान महिला नधि औपचारिक बैंकों के साथ एक पूरक वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करेगा। इस नधि का संचालन एसएचजी की महिलाओं के द्वारा एसएचजी की महिलाओं के लिये ही किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में महिलाओं द्वारा संचालित बैंक स्थापित किये जाने के संबंध में घोषणा की गई थी।